

दिल्ली शिक्षा क्रान्ति : 'प्रगति' शृंखला

अंजू घावरी



जब से वर्तमान शासन ने राजनीतिक नेतृत्व सम्हाला है तब से दिल्ली की सरकारी शिक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन करने का दौर बड़े पैमाने पर चल रहा है। जो पिछले पन्द्रह वर्षों से इस तंत्र (सिस्टम) से जुड़ा है, वह दिल्ली की सरकारी शिक्षा प्रणाली के पुनरुद्धार की यात्रा को खूबसूरती के साथ रूपायित कर सकता है। यह यात्रा अभूतपूर्व है।

जब मैंने 2003 में एक सरकारी स्कूल में प्राथमिक शिक्षक के रूप में कार्य करना शुरू किया, तब से दिल्ली सरकार के स्कूली तंत्र को एक 'इनसाइडर' के तौर पर नज़दीक से देखा है। मैं 2008 में गणित की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षिका बनी और वर्तमान में वाणिज्य विषय की व्याख्याता के रूप में काम करने के साथ-साथ एक मेंटर शिक्षिका के कार्य से भी जुड़ी हूँ। 'मेंटर शिक्षिका' दिल्ली सरकार का एक प्रमुख प्रोजेक्ट है जिसके अन्तर्गत शिक्षा विभाग में शैक्षिक और प्रणालीगत बदलाव लाने के लिए अतिउत्प्रेरित और प्रतिबद्ध 200 शिक्षकों की एक टीम गठित की जाती है।

तो आइए, वहाँ से शुरू करें, जब बेहद खराब बुनियादी ढाँचे और गन्दगी से दिल्ली के सरकारी स्कूलों को पहचाना जाता था। स्कूल बड़े दयनीय नज़र आते थे और शिक्षक व शिक्षार्थी दोनों वहाँ जाना पसन्द नहीं करते थे। शिक्षा और विषय-सामग्री के निष्पादन की गुणवत्ता इस हद तक कम हो गई थी कि 2015-16 के दौरान कक्षा नौवीं में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या केवल 49% थी। इन समस्याओं की विकराल प्रकृति के सामने सभी हितधारक असहाय महसूस कर रहे थे। रणनीतिक रूप से अच्छे समन्वित सुधारों की एक शृंखला की तत्काल आवश्यकता थी।

नव निर्वाचित सरकार ने स्थिति को सम्हाला और

कुछ ऐसे सलाहकार निकायों, जिनके पास इस क्षेत्र में समृद्ध अनुभव था, को भागीदारी के लिए आमंत्रित किया। पहले वर्ष में प्रणाली के हार्डवेयर को पुनर्जीवित करने का काम हाथ में लिया गया। नई इमारतों और कक्षाओं का निर्माण किया गया और अन्य विभिन्न भौतिक सुविधाओं जैसे स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, शौचालय की सुविधा, हवादार कक्षा-कक्ष और प्रयोगशालाओं पर ध्यान दिया गया। दो अतिरिक्त पद बनाए गए जिसमें एक सम्पत्ति प्रबन्धक (एस्टेट मैनेजर) का पद था जो स्कूल के भवन और सम्पत्ति का ध्यान रखे और एक वेतन प्रबन्धक का पद जो प्रशासनिक कार्यों जैसे कि वेतन बिल बनाने और शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों के आधिकारिक रिकॉर्ड रखने में सहायता करे। अगले वर्ष में सॉफ्टवेयर प्रणाली को अद्यतन करने की योजना बनाई गई थी। हम इस महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में बात करेंगे और साथ ही यह भी देखेंगे कि स्कूलों के शैक्षिक माहौल का ध्यान किस तरह से रखा गया।

जब तक बीमारी का सही निदान न किया जाए तब तक इलाज शुरू नहीं किया जा सकता था। इसलिए पहला क़दम मूल कारणों और कमियों की सीमा का पता लगाना था। कक्षा छह और सात के विद्यार्थियों की पढ़ने की क्षमता और बुनियादी गणितीय क्षमता की जाँच करने के लिए 1000 से अधिक सरकारी स्कूलों में बेसलाइन मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की गई। जो परिणाम सामने आए वे अत्यन्त अप्रत्याशित थे। 50% से अधिक विद्यार्थी अपनी निर्धारित पाठ्यपुस्तकों को पढ़ ही नहीं सके और उनमें बुनियादी गणितीय साक्षरता की भी कमी थी। हस्तक्षेप के पहले वर्ष में इस तरह के विद्यार्थियों के लिए विषय-सामग्री की पढ़ाई को रोक, पठन कक्षाएँ संचालित करने और बुनियादी गणितीय साक्षरता प्रदान करने का निर्णय लिया गया। यदि कोई बच्चा

पाठ्यपुस्तक भी नहीं पढ़ पा रहा है तो उससे यह अपेक्षा कैसे की जा सकती है कि वह अधिगम की प्रक्रिया का आनन्द लेगा और वांछित परिणाम लेकर आएगा? कुछ महीनों तक इन बच्चों के साथ कड़ी मेहनत की गई और उसके सकारात्मक परिणाम सामने आए।

अगला कदम यह था कि उन्हें पाठ्यपुस्तकों की सहायता से और फैसिलिटी के रूप में शिक्षक की भूमिका से अपने विषय सम्बन्धी ज्ञान का निर्माण करने में सक्षम बनाया जाए।

समय की माँग यह थी कि एक ऐसी सामग्री विकसित की जाए जो इन नए पाठकों के लिए सरल हो। यह महसूस किया गया कि जिन पाठ्यपुस्तकों का अभी उपयोग किया जा रहा है उनकी शैली और भाषा उचित नहीं है क्योंकि इन विद्यार्थियों ने हाल ही में पढ़ना सीखा था। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि एक सरलीकृत संसाधन और सहायक सामग्री विकसित की जाए जिनकी भाषा सरल हो और जिनमें विषय-सामग्री के साथ दृश्य और चित्र भी दिए गए हों ताकि ये नए पाठक विषय की इन पुस्तकों में रुचि लें। इन पुस्तकों को प्रगति यानी विकास नाम दिया गया था। विभाग के अंग्रेजी, हिन्दी और गणित के विषय विशेषज्ञों के साथ मिलकर पुस्तकों की पहली शृंखला विकसित की गई थी। पुस्तक के बारे में शिक्षकों की ओर से मिश्रित प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। प्रमुख आलोचना यह थी कि इन पुस्तकों में सन्दर्भ की कमी थी और शिक्षकों ने सोचा कि जो लोग विद्यार्थियों के साथ काम नहीं करते हैं, उनकी तुलना में वे स्वयं एक बेहतर सामग्री विकसित कर सकते हैं क्योंकि वे विद्यार्थियों के सीखने के अन्तराल को ठीक से जानते हैं।

विभाग ने इस फीडबैक को सकारात्मक तरीके से लिया और यह निर्णय लिया कि शिक्षकों द्वारा स्वयं एक और शृंखला विकसित की जाए। यहाँ विभाग के प्रयास सराहनीय हैं क्योंकि इसने ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले हितधारकों के फीडबैक पर ध्यान दिया और हज़ारों शिक्षकों को साथ जोड़ने के विशाल कार्य को करने का निर्णय लिया।

यह समय सभी शिक्षकों के साथ सहयोग करने और

एक ऐसी प्रणाली बनाने का था जिसमें नए पाठकों को ग्रेड के अनुसार अधिगम-परिणामों को प्राप्त करने में मदद दी जा सके। 2016-17 की गर्मियों की छुट्टियों के दौरान सभी शिक्षकों के लिए एक बड़े स्तर की कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला को विषय-वार आयोजित किया गया जहाँ समान-विषय के सभी शिक्षकों को एक समूह में बैठकर रणनीतियों को डिज़ाइन करने के लिए कहा गया। शिक्षकों का एक सामान्य फ़ीडबैक यह था कि एनसीईआरटी और दिल्ली ब्यूरो ऑफ़ टेक्स्टबुक्स द्वारा प्रदान की गई पाठ्यपुस्तकों को विद्यार्थियों के लिए फिर से प्रासंगिक किया जाना चाहिए। शिक्षकों ने महसूस किया कि विषय-सामग्री के परिवेश, पुस्तक की भाषा और पाठ के अन्त में दिए गए प्रश्नों को दिल्ली के सन्दर्भ में सरल और सुबोध तरीके से फिर से लिखना चाहिए। शिक्षकों ने सर्वसम्मति से महसूस किया कि सरकारी स्कूल समाज के सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित तबके के लिए है जहाँ के अधिकतर बच्चों के घरों में अधिगम के लिए आवश्यक अनुकूल वातावरण नहीं होता। बच्चों को एक सहायक पुस्तक देने का निर्णय लिया गया जो उनके विशिष्ट अधिगम रिक्रियों और ज़रूरतों को पूरा कर सके। साथ ही ऐसी प्रासंगिक सामग्री कम समय और प्रयास के साथ कक्षा में सन्दर्भ विकसित करने में शिक्षकों की सहायता करेगी। इसका कारण यह था कि सहायक सामग्री में जो भी उदाहरण और परिस्थितियाँ पहले से मौजूद थीं, वे विषय-सामग्री को बच्चों तक पहुँचाने में शिक्षकों की सहायता करेगी।

हज़ारों शिक्षकों ने एक साथ बैठकर विषय-सामग्री, वर्कशीट्स और प्रेज़ेंटेशन बनाए जिन्हें सम्पादित करके सहायक सामग्री के रूप में एक साथ रखा गया। सम्भवतः ऐसा पहली बार हुआ कि शिक्षकों को किसी ऐसे बाहरी व्यक्ति द्वारा तैयार की गई पुस्तक नहीं दी गई, जिसे सामाजिक-सांस्कृतिक ताने-बाने और विद्यार्थियों के सीखने के तरीके का ज्ञान न हो। वास्तव में, शिक्षकों ने स्वयं से अपनी सामग्री तैयार की जो पारम्परिक तरीकों का पालन करने के बजाय रचनात्मक शिक्षाशास्त्र पर आधारित थी।



नतीजतन, इन सन्दर्भपरक पुस्तकों ने कक्षा के संवाद को नई गति दी क्योंकि शिक्षकों ने अपने विषय समूहों के भीतर सक्रिय रूप से अपने विषय के प्रत्येक टॉपिक पर विचार-मन्थन किया। यह प्रक्रिया दो तरह से फ़ायदेमन्द साबित हुई। पहला, इसने विद्यार्थियों को उनके अधिगम की ज़रूरतों के अनुसार सामग्री दी। दूसरा, इसने शिक्षकों की पेशेवर क्षमता और शैक्षणिक प्रवृत्ति में मदद की क्योंकि उन्होंने अपने-अपने विषय समूहों में बातचीत की जिसके कारण किसी टॉपिक को सर्वोत्तम रूप से पढ़ाने पर काफ़ी चर्चा और बहस हुई।

इन पुस्तकों को तुरन्त सफलता मिली। चूँकि शिक्षक खुद इस प्रक्रिया में जुड़े हुए थे इसलिए उनके मन में भी पुस्तकों के प्रति विभाग जितना ही स्वामित्व का भाव था। अपने काम को एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित देखकर शिक्षक बहुत प्रफुल्लित हुए। अपनेपन और स्वामित्व की इस भावना ने कक्षा के कार्यकलापों में उनके उपयोग को बहुत प्रोत्साहन दिया। इसके अलावा यह सामग्री विद्यार्थियों के भी अनुकूल थी चूँकि यह उन्हीं के शिक्षकों द्वारा विकसित की गई थी। विद्यार्थियों ने अपनी गति से और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अवधारणाओं को सीखा। इसके परिणाम वार्षिक मूल्यांकन में देखने को मिले। जिन विद्यार्थियों को पहले नज़रअन्दाज़ कर उन पर कमज़ोर होने का ठप्पा लगा दिया गया था, वे अब अपनी पाठ्यपुस्तकों को पढ़ पा रहे थे और अवधारणाओं को अपने शब्दों में समझा पा रहे थे। इस समूह के लिए सामग्री को सरल बनाने के अलावा पाठ्यक्रम भी कम कर दिया गया था। यह महसूस किया गया कि इस नव-साक्षर समूह के लिए अवधारणाओं की मात्रा को कम करना ज़रूरी था ताकि पिछले वर्षों में उनके सीखने में जो कमी हुई है उसकी भरपाई के लिए उन्हें उत्तरोत्तर सीखने में मदद मिल सके। वर्तमान आँकड़ों के अनुसार पढ़ने में

कठिनाई होने वाले बच्चों का प्रतिशत अब काफ़ी कम हो गया। इस समूह में विशेष बच्चे, सीखने में कठिनाई अनुभव करने वाले और लम्बे समय से अनुपस्थित रहने वाले बच्चे शामिल हैं।

हालाँकि कक्षा-शिक्षण को बेहतर बनाने और शिक्षण-अधिगम की प्रस्तुति को उपदेशात्मक से रचनात्मक में बदलने के लिए बहुत कुछ किया गया है, किन्तु सरकारी स्कूलों में सीखने की गुणवत्ता में सुधार के लिए अभी भी बहुत कुछ करना बाक़ी है। छात्र-शिक्षक अनुपात का अधिक होना और स्कूल के प्रशासनिक कार्यों जैसे शुल्क संग्रहण, प्रशासनिक रिकॉर्ड बनाए रखना, मध्याह्न भोजन का वितरण व निरीक्षण करना आदि की व्यस्तता में शिक्षकों के शिक्षण का क्रीमती समय चला जाता है और उनकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा पर भी असर होता है। इसके अतिरिक्त यह भी सत्य है कि स्कूल के प्रधानाध्यापक भी अधिकतर प्रशासनिक अधिकारियों के रूप में काम करते हैं और उनमें आवश्यक शैक्षिक नेतृत्व की कमी होती है जिसकी वजह से स्कूल लघु प्रशासनिक इकाइयाँ नज़र आने लगते हैं न कि एक प्रगतिशील अधिगम संगठन।

वर्तमान सरकार ने सरकारी क्षेत्र में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अथक परिश्रम करने के साथ शिक्षा के क्षेत्र में समृद्ध अनुभव रखने वाले विभिन्न गैर-सरकारी निकायों को सलाहकार के रूप में जोड़ा है। ऐसा ही एक संगठन है- क्रिएटनेट (CREATNET) जो स्कूल नेतृत्व विकसित करने के लिए प्रधानाचार्यों और शिक्षकों के साथ मिलकर काम करता है। हमें उम्मीद है कि निरन्तर प्रयास और ईमानदार इच्छा से प्रचालन-तंत्र व शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार कर हम हर सरकारी स्कूल को शिक्षण संगठन के रूप में देख पाएँगे।

अंजू घावरी शिक्षा निदेशालय, दिल्ली के तहत एक सरकारी स्कूल में स्नातकोत्तर शिक्षिका हैं। उनके पास अध्यापन का 15 वर्षों का अनुभव है और वे मेंटर शिक्षिका भी हैं जो अन्य शिक्षकों की सहायता करती हैं। उन्हें नेतृत्व और गणित कार्यक्रमों का वैश्विक अनुभव प्राप्त है। उनसे anjughavri@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है।

अनुवाद : नलिनी रावल पुनरीक्षण : प्रीति मिश्रा कॉपी एडिटर : ज्योति चौरड़िया